Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume -8 Issue-4 February - 2025
Total Pages - 28 Price - Rs. 10

Budget-2025

जन आकांक्षाओं पर कितना खरा !

केंद्रीय बजट-2025

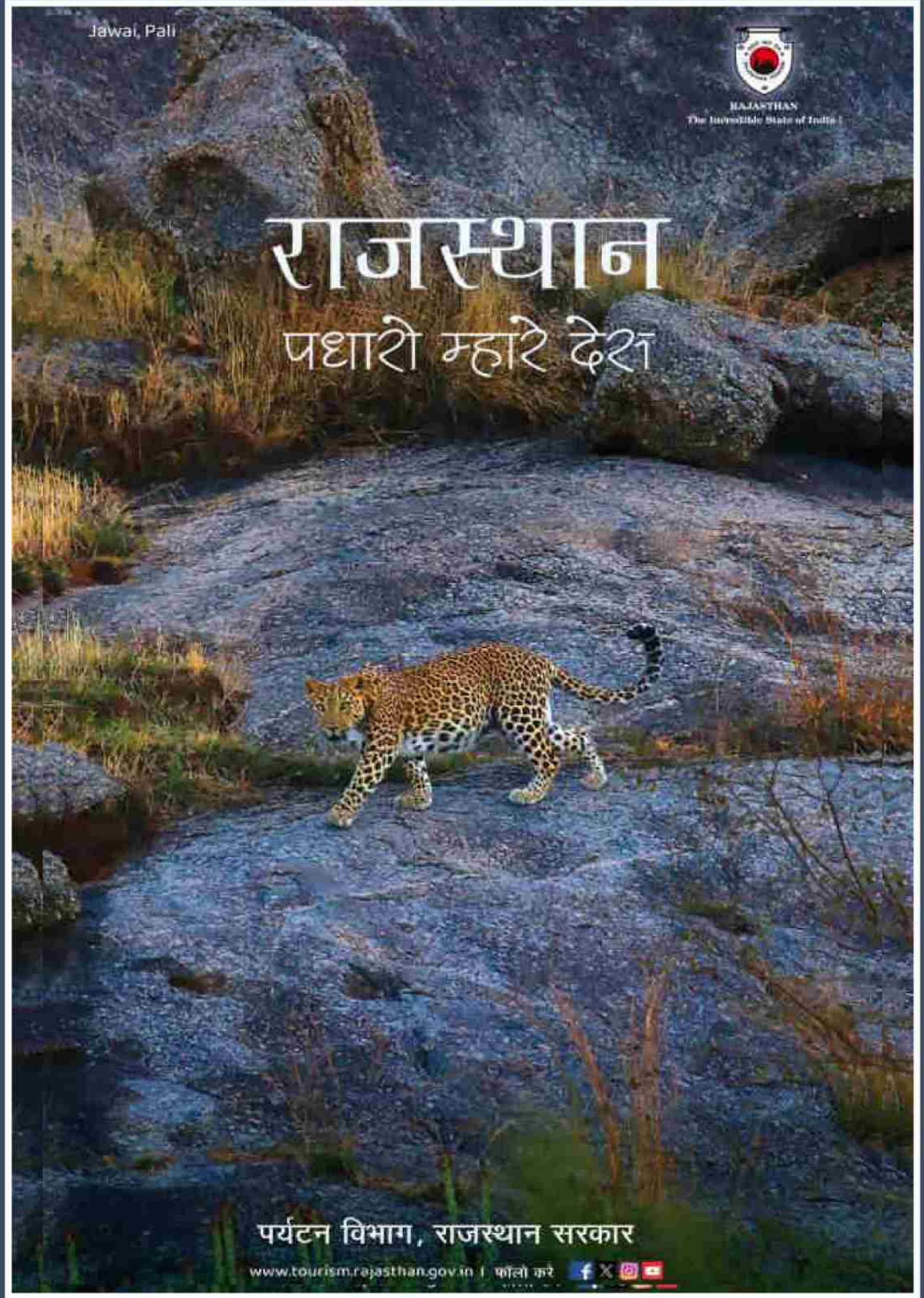
Jawai, Pali
RAJASTHAN
The Incredible State of India !
राजस्थान
पधारो म्हारे देश
पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार
www.tourism.rajasthan.gov.in | फॉलो करें

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -8 Issue - 4 February 2025

Editorial Board

■ *Patron*

Shri Ghanshyam Ojha, National President	098290-22896
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

■ *Editor*

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

■ *Co-Editor*

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial.....	03
हम अपनी आंखों से भारत को	04
केंद्रीय बजट 2025–26	07
मंत्रालय को पत्र	11
Artificial Intelligence	13
Advantage Assam	15
राजस्थान राज्य बजट–2025	17
लघु उद्योग भारती का क्षेत्रीय सम्मेलन	19
विज्ञान का संचार	21
News Update	23

Price - 10/- *Life Membership 1000/-*

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal
Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582
Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

Budget 2025 and MSMEs: Is Ahead to Betterment?

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the first full budget of Modi government 3.0. The foremost reform announced in the Budget is the increase in investment and turnover limits for MSME classification, raising them by 2.5 times and 2 times, respectively. I think this move will provide MSMEs with greater access to resources and encourage technological adoption. By revising these limits, the government aims to ensure that growing the benefits for MSMEs. Having said that, without a streamlined regulatory framework and effective monitoring mechanisms, these revisions might remain largely ineffective and may sadly remain mere announcements. A larger classification pool also means increased competition for government benefits to beneficiaries to be able to reap the rewards.

Nevertheless, the Budget also announced substantial improvements in credit access. The credit guarantee cover for micro and small enterprises has been doubled from ₹5 crore to ₹10 crore, enabling additional credit of ₹1.5 lakh crore over five years. Startups will benefit from an increased guarantee cover of ₹20 crore, and exporters can avail term loans up to ₹20 crore with enhanced guarantees. Additionally, the introduction of credit cards for micro enterprises under the Udyam portal is a commendable step, offering ₹5 lakh in credit to small businesses.

Another notable initiative is the ₹10,000 crore Fund of Funds for startups and a dedicated scheme for first-time women, Scheduled Caste, and Scheduled Tribe entrepreneurs. By providing term loans up to ₹2 crore over five years, this scheme builds upon the successes of the Stand-Up India initiative.

It is true and everyone agrees that the sector is a crucial employment generator, and the budget has rightly focused on labour-intensive industries such as footwear, leather, and toys. The new Focus Product Scheme aiming to create 22 lakh jobs and to generate a turnover of ₹4 lakh crore, is commendable. Additionally, a cluster development initiative for the toy industry is expected to position India as a global manufacturing hub.

While these initiatives could provide a much-needed boost, I believe the real challenge is in execution. Many MSMEs in these sectors face issues like outdated production methods, inadequate infrastructure, and global competition. Without parallel investments in skill development and supply chain improvements, these measures may fail to deliver the intended results.

No doubt the Budget presents a well-rounded strategy to empower MSMEs, but its success will depend on its implementation, accessibility. The revised classification criteria and credit enhancements will only be effective if they translate into tangible benefits for businesses on the ground. Similarly, while sector-specific initiatives are well-intentioned, they need robust infrastructure and skill development programs to sustain their impact. The success of this year's Budget announcements will hinge on how seamlessly financial institutions implement them.

I invite your opinions.

□□□

'हम अपनी आंखों से भारत को 'विश्व गुरु' बनते हुए देखेंगे'

(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवनिर्मित भवन केशव कुंज का प्रवेशोत्सव 19 फरवरी को मनाया गया)

प्रवेशोत्सव

उद्योग टाइम्स डेस्क

दिल्ली के झंडेवालान में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय 'केशव-कुंज' के पुनर्निर्मित भवन के प्रवेशोत्सव पर पूज्य सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने अपने प्रेरक पाथेय से संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।

श्री भागवत ने कहा कि संघ की दशा बदली है, लेकिन दिशा नहीं। समृद्धि की आवश्यकता है, इसलिए जितना आवश्यक है उतना वैभव होना चाहिए, लेकिन ऐसा मर्यादा में रहकर करना चाहिए। श्री केशव स्मारक समिति का यह पुनर्निर्मित भवन भव्य है, इसकी भव्यता के अनुरूप ही संघ का कार्य खड़ा होना चाहिए। देश में आज संघ का कार्य गति पकड़ रहा है। हमें इस भवन की भव्यता के अनुरूप ही संघ के कार्य को भव्य बनाना है। संघ का कार्य पूरे विश्व तक जाएगा जो भारत को विश्वगुरु के पद पर आसीन करेगा। और हम अपनी इसी देह, इन्हीं आखों से भारत को विश्व गुरु बनते देखेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। हमें इसके लिए कार्य को सतत विस्तार देना होगा।'

उन्होंने इस अवसर पर संघ के आरम्भ से आद्य सरसंघचालक द्वारा झेली गई अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया। नागपुर में पहले कार्यालय महाल की शुरुआत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश का संचालन यहीं से होता है, इसलिए एक कार्यालय की आवश्यकता दिल्ली में महसूस हुई। आज यह भव्य भवन बन जाने भर से स्वयंसेवक का काम पूरा नहीं होता। हमें ध्यान रखना होगा कि कि उपेक्षा और विरोध हमें सावधान रखता है, लेकिन अब अनुकूलता का वातावरण है हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सरसंघचालक जी ने कहा कि कार्यालय हमें कार्य की प्रेरणा देता है, लेकिन उसके वातावरण की चिंता करना प्रत्येक स्वयंसेवक का कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि आज संघ के विभिन्न आयामों के माध्यम से संघ कार्य विस्तृत हो रहा है। इसलिए अपेक्षा है कि संघ के स्वयंसेवक के व्यवहार में सामर्थ्य और शुचिता बनी रहे।

समारोह में श्रीराम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य श्री गोविंददेव गिरी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि आज श्री गुरुजी की जयंती है, इसलिए पावन दिन है। आज शिवाजी की भी जयंती है। शिवाजी संघ की विचार शक्ति हैं। कांची कामकोटि पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य परमाचार्य ने एक बार एक वरिष्ठ प्रचारक से कहा था कि संघ प्रार्थना से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। श्री गोविंददेव गिरी ने छावा फिल्म का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्रपति ने ऐसे मावले तैयार

किए, जो थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते नहीं। संघ के स्वयंसेवक छत्रपति शिवाजी के तपोनिष्ठ मावलों सरीखे ही हैं। हम हिन्दू भूमि के पुत्र हैं, संघ राष्ट्र की परंपरा को पुष्ट करते हुए राष्ट्र की उन्नति की बात करता है।

उदासीन आश्रम दिल्ली के प्रमुख संत श्री राघवानंद महाराज ने अपने संक्षिप्त आशीर्वचन में कहा कि संघ 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो इसके पीछे डॉक्टर साहब का प्रखर संकल्प ही है। संघ ने समाज के प्रति समर्पण भाव से कार्य किया है समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। इसलिए संघ कार्य सतत बढ़ रहा है।

केशव स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने शुरू से लेकर अब तक के केशव कुंज के पुनर्निर्माण के विभिन्न पड़ावों की विस्तार से जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 1939 से ही संघ का काम रहा है। तब झंडेवालान में इसी स्थान पर एक छोटा–सा भवन बनाया गया था जिसमें संघ कार्यालय का कुछ हिस्सा बना था। लेकिन आगे 1962 में इसका विस्तार करके अन्य कक्ष बनाए गए थे। 1969 में श्री केशव स्मारक समिति का गठन हुआ। 80 के दशक में आवश्यकता के अनुसार भवन का और विस्तार हुआ। वर्ष 2016 में पूज्य सरसंघचालक जी ने ही अपने कर–कमलों से इसी स्थान पर पूजा अनुष्ठान के साथ श्री केशव स्मारक समिति के द्वारा निर्मित केशव कुंज के तीन टावर वाले इस भवन का शिलान्यास किया था। और आज यह पुनर्निर्मित स्वरूप में हम सबके सामने है।

केशव कुंज में मुख्यतः तीन टावर है– साधना, प्रेरणा और अर्चना। एक आकर्षक और आज की सभी आवश्यकताओं से परिपूर्ण अशोक सिंघल सभागार भी है आम जन के लिए एक केशव पुस्तकालय है ओपीडी चिकित्सालय है और साहित्य भंडार है। सुरुचिपूर्ण और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पुस्तकों के लिए सुरुचि प्रकाशन है। केशव कुंज की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग के लिए 150 किलोवाट का सोलर प्लांट है, कचरे के उचित निस्तारण रीसाइक्लिंग के लिए 140 केएलडी क्षमता का एसटीपी प्लांट है। पूर्व की तरह ही नूतन भवन में एक सुंदर दिव्य हनुमान मंदिर है। कार्यक्रम में ऐसे कुछ सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधि रूप में सम्मान किया गया जिन्होंने भवन के निर्माण में विविध कार्यों में योगदान दिया है।

मंच पर सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबोले, उत्तर क्षेत्र संघचालक श्री पवन जिंदल, दिल्ली प्रांत संघचालक डॉ. अनिल अग्रवाल भी उपस्थित थे। प्रवेशोत्सव में संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, श्री अरुण कुमार, वरिष्ठ प्रचारक श्री सुरेश सोनी, सम्पर्क प्रमुख श्री रामलाल, सह प्रचार प्रमुख श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री इंद्रेश कुमार, श्री प्रेम गोयल, श्री रामेश्वर, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा, सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे।

□□□

LUB's Delegation urges Commerce Minister to Stop Import Gypsum Powder

LUB's Delegation of Bikaner unit led by National Organising Secretary Shri Prakash Chandra ji, and National General Secretary Shri Om Prakash Gupta met Union Minister for Commerce Shri Piyush Goyal to stop the import of Gypsum Powder from Egypt. A request was also made to restart the payment of GST of the oil mill which has been stopped since 2021 and assurance was given to take appropriate action. On this occasion, Bikaner Unit President Shri Harsh Kansal, State Vice President Balkishan Parihar and other office bearers were also present.

Bahraich Unit Conducts Workshop for Entrepreneurs

LUB's Bahraich Unit & UPICON Lucknow jointly conducted an ESG Workshop to inform entrepreneurs about product and export promotion, branding, improving packaging processes, building private industrial parks, GST, easy subsidy process and discharging their social responsibilities at Lucknow on 19 February, 2025.

Malegaon Unit organized the Inaugural Ceremony

LUB's Malegaon Unit organized the Inaugural Ceremony on 29 January in the presence of Education Minister Shri Dadasaheb Bhuse, Maharashtra and LUB State President Shri Ravindra Vaidya. On this occasion, members from Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon and Ahilyanagar districts participated. Speakers emphasized on regional industrial development, opportunities and challenges..

Udyog Darshan @ Udaipur

LUB's Udaipur Unit of Rajasthan State conducted Udyog Darshan at Ficusa Enterprises on 26 February, 2025. Promoter Shri Pawan Kothari introduced the unit which deals with refurbishment of Business Class Branded Desktop, Laptop, Projectors, Workstations, and Servers. 45 members joined this unique industrial visit

Workshop on Millets @ Jodhpur

LUB's Jodhpur Women Wing conducted a One Day Workshop on the utility of Millets at Ratanada. Wing President Smt. Mona Harwani discussed the significance of Millets for health.

भारतीय जन-आकांक्षाओं पर आखिर कितना खरा उतरा !

केंद्रीय बजट 2025-26

विश्लेषण

अश्वनी महाजन
जाने-माने अर्थ चिंतक एवं
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर
ashwanimahajan@rediffmail.com

जबकि पिछली दो तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि में मंदी, रुपये में गिरावट, लगातार मुद्रास्फीति, खपत में कमी, बढ़ता व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं, सरकार के लिए विनिर्माण वृद्धि, कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, किसानों का समर्थन और कृषि उत्पादन में असंतुलन को दूर करना, दालों और खाद्य तेलों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम करना, मध्यम आय वाले करदाताओं को कर में राहत देना और साथ ही मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को दूर करना वास्तविक चुनौती थी। बजट 2025–26 ने इन सभी चिंताओं को संतुलित करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

लेकिन, यह भी सही है कि तमाम बाधाओं के बावजूद, देश की राजकोषीय सेहत काफी अच्छी स्थिति में थी। कम राजकोषीय घाटा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों में उछाल, भारी मात्रा में एनआरआई प्रेषण और चालू वित्त वर्ष में निवेश की घोषणाओं में वृद्धि वित्त मंत्री के काम को आसान बना रही थी। इससे वित्त मंत्री को छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विनिर्माण के लिए अधिक प्रावधान करने के अलावा बड़े पूंजीगत व्यय जारी रखने की गुंजाइश मिल सकी।

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत-

हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार आयकर के मामले में मध्यम वर्ग को कुछ राहत पहले से भी दे रही थी, लेकिन कहानी यह रही है कि हर बजट में मध्यम वर्ग को बहुत कम लाभ मिलता है। लेकिन मोदी 3.0 में अपने पहले पूर्ण बजट में, वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को, 12 लाख रुपये की वार्षिक आय या एक लाख रुपये की मासिक आय तक किसी भी कर का भुगतान करने से मुक्त करके वास्तव में बड़ी राहत दी है। वेतनभोगी वर्ग के मामले में, यह छूट 12.75 लाख है, क्योंकि उन्हें अपनी आय से 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलता है। हालांकि, 12 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोग उतने भाग्यशाली नहीं हैं, हालांकि, एक लाख रुपये मासिक आय वाले लोगों जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन उन्हें भी कुछ राहत जरूर मिली है।

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा-

आत्मनिर्भर भारत नीति की शुरुआत के बाद से, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट 2025–26 में विनिर्माण को बढ़ावा देने का विशेष प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और मोटर, पवन ऊर्जा उपकरण और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण शामिल हैं।

एमएसएमई विनिर्माण मिशन, एमएसएमई के लिए बढ़ी हुई

ऋण गारंटी; उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड; पहले की सूची से आगे पीएलआई योजना का विस्तार; और देश को चीनी प्रभुत्व से बचाने के लिए विनिर्माण में सुधार के लिए कई अन्य उपाय इस बजट की महत्वपूर्ण पहल हैं। सरकार का वर्तमान प्रयास भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक वृहत कार्य करेगा, और वह भी एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से।

इस बजट में लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और अन्य स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वच्छ तकनीक मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयातित बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और सौर सेल के लिए विदेशों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण हमारा आयात बिल बढ़ रहा है और भविष्य में आयातित घटकों पर हमारी निर्भरता के कारण देश का शोषण भी हो सकता है। इसलिए, यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है और देश को विदेशियों, विशेष रूप से चीन द्वारा शोषण से बचा रहा है। एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, स्टार्ट–अप के लिए विभिन्न योजनाएं, भारत को दुनिया का 'खिलौना हब' बनाने के लिए खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन, बजट की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं।

एमएसएमई को प्रोत्साहित करना–

बजट सभी स्तरों पर एमएसएमई, स्टार्ट–अप और निर्यात उन्मुख इकाइयों को बढ़ा हुआ ऋण गारंटी कवर देकर एमएसएमई क्षेत्र को नया बढ़ावा देता है; श्रम गहन क्षेत्रों, विशेष रूप से चमड़ा और जूते क्षेत्र, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य के लिए उपाय। विशेष रूप से विनिर्माण मिशन, छोटे, मध्यम, बड़े; सभी प्रकार के उद्योगों को शामिल करते हुए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।

कृषि को बढ़ावा–

बिहार के एक अद्भुत पौष्टिक कृषि उत्पाद मखाना को बढ़ावा देने की दिशा में 'मखाना बोर्ड' का गठन अनुकरणीय कदम है और इससे अन्य क्षेत्रों के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। हाल ही में, सरकार ने हल्दी बोर्ड का गठन भी किया है, जिसकी मांग स्वदेशी जागरण मंच यूपीए के दिनों से ही कर रहा था, ताकि तेलंगाना के हल्दी किसानों की चिंताओं को दूर किया जा सके। दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम, कपास मिशन और कृषि के लिए कई अन्य योजनाएं सराहनीय हैं। कई अन्य उपायों के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना भी संतोषजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों से आबादी को स्थानांतरित करने की अनिवार्यता के बयानबाजी के विपरीत, शायद निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में यह कहना अच्छा लगा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन एक विकल्प ही हो, लेकिन अनिवार्यता नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के बढ़ते अवसरों के साथ, सरकार के प्रयासों की बदौलत यह एक संभावना हो सकती है।

ग्रामीण और शहरी भारत के बीच अंतर को पाटना–

देश के सामने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आय की असमानता एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह रिपोर्ट आने पर संतोष हुआ कि ग्रामीण और शहरी आबादी में एमपीसीई (मासिक प्रति व्यक्ति व्यय) के बीच का अंतर 84 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत हो गया है। यह ग्रामीण सड़कों, आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, पानी, बिजली,

स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण संभव हुआ है। इस प्रक्रिया को और तेज करने की आवश्यकता है।

बजट 2025–26 ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के अलावा, कृषि को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और ग्रामीण आय बढ़ाने के कई अन्य प्रयास ग्रामीण–शहरी असमानताओं को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य परिदृश्य में सुखद बदलाव: सरकार ले रही है अधिक जिम्मेदारी-

केंद्रीय बजट 2025–26 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और स्वास्थ्य अनुसंधान पर 103280 करोड़ रुपये का व्यय आवंटित किया गया है। यदि हम पिछले 11 वर्षों पर नजर डालें, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और स्वास्थ्य अनुसंधान पर व्यय में 8.3 गुना वृद्धि हुई है, जो 2014–15 में 12482 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट 2025–26 में 103280 करोड़ रुपये हो गया है। इस अवधि के दौरान केंद्रीय बजट का आकार मुश्किल से 2.8 गुना ही बढ़ा है।

दस साल पहले, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.0 प्रतिशत ही था। उल्लेखनीय है कि 1990–91 में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक व्यय (जिसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पोषण, बाल और विकलांग कल्याण शामिल होते हैं) सकल घरेलू उत्पाद का 2.36 प्रतिशत था। वैसे तो भारत में सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान कभी भी उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन एलपीजी से पहले के दौर में भी इन सुविधाओं को सरकारी नीति–निर्माण के केंद्र में रखा जाता रहा। एलपीजी नीतियों के तहत निजीकरण के आगमन के साथ ही लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ दिया गया। 2014–15 से पहले जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कम होती जा रही थीं, उनमें काफी सुधार होना प्रारंभ हुआ है, जिससे लोगों द्वारा जेब से किए जाने वाले खर्च को कम करना संभव हो पाया है। हम देखते हैं कि 2004 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय 4.2 प्रतिशत था, और इसमें से 2.59 प्रतिशत निजी जेब से किए जाने वाले खर्च का था। जैसा कि 2015 की भारत सरकार की रिपोर्ट में कहा

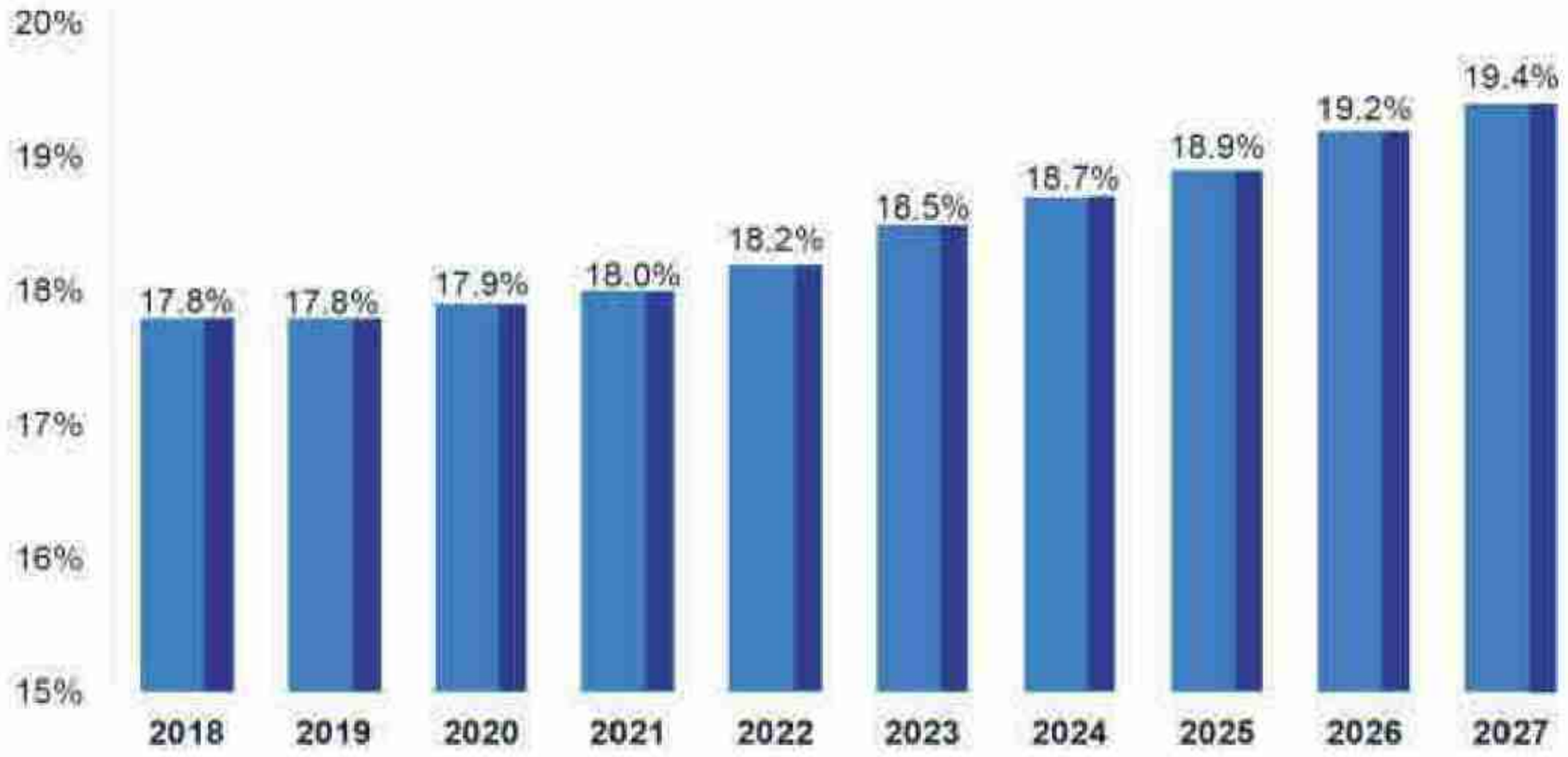

Sources: Centers for Medicare & Medicaid Services. National Health Expenditure Projections 2018-2026, Forecast Summary and Selected Tables

गया है, "स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण व्यय भयावह रूप से बढ़ रहा है और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गरीबी में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण परिवार की आय पर पड़ने वाला असर आय में वृद्धि के लाभ और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजना को बेअसर कर सकता है।" पिछले एक दशक में सरकार द्वारा सकारात्मक और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के कारण, गैर–संचारी रोगों के बढ़ते मामलों के बावजूद, जेब से होने वाले खर्च में लगातार कमी आ रही है, जिससे आम जनता और खास तौर पर गरीबों को राहत मिली है।

2013–14 तक जेब से होने वाला खर्च करीब 2.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहा। 2004–05 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जेब से होने वाला खर्च 2.58 था, जो 2013–14 में भी 2.43 पर बना रहा, जबकि तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में बड़े–बड़े दावे किए थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के साथ, हमने निजी जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय में धीरे–धीरे गिरावट देखी है। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जेब से किये जाने वाले व्यय में अधिक तेजी से गिरावट 2015–16 के बाद देखी गई, क्योंकि यह 2015–16 में 2.32, 2019–20 में 1.54, 20–21 में 1.66 और 21–22 में 1.55 थी।

भारत के मामले में, आयुष्मान भारत की शुरुआत ने निजी जेब से स्वास्थ्य खर्च कम करने में काफ़ी मदद की है। आयुष्मान भारत योजना में दो खंड शामिल हैं– एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन और निर्माण से संबंधित है जिसे प्रधानमंत्री–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम–एबीएचआईएम) के रूप में जाना जाता है और दूसरा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की दिशा में है जिसे आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई) के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2024 तक, कुल 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) या तो स्थापित किए गए थे या मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप–स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) से उन्नत किए गए।

गिग वर्कर्स-

इस बजट में ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले गिग वर्कर्स को मान्यता देने, उन्हें ई–श्रम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने और उन्हें स्वास्थ्य कवर का लाभ देने के अलावा श्रम गहन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का काम किया गया है। लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग कर रहे थे।

□□□

लघु उद्योग भारती ने केंद्रीय बजट में एमएसएमई वर्गीकरण के विरोध और सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के हित में लिखा मंत्रालय को पत्र

निर्देशक अंक ल.उ.भा./2024–25/933

श्री एस. सी. एल. दास
सचिव,
एमएसएमई मंत्रालय,
भारत सरकार,
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

विषय- केंद्रीय बजट-2025 में एमएसएमई के वर्गीकरण को संशोधित करने के प्रस्ताव के संबंध में।

मान्यवर,

लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एसएमई) के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए समर्पित एक अखिल भारतीय संगठन है। 581 जिलों में मजबूत उपस्थिति और लगभग 53,000 सदस्यों के साथ, हम देश भर में एसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं।

केन्द्रीय बजट–2025 पेश करते समय निवेश के संबंध में एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड को 2.5 गुना संशोधित करने और टर्नओवर के मामले में दोगुना करने का प्रस्ताव किया गया है, जो मौजूदा जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं लगता है। एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2023–24 की रिपोर्ट को देखने पर पता चलता है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSS) द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, देश में 633.88 लाख असंगठित गैर–कृषि एमएसएमई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

सूक्ष्म	**:**	**630.52 लाख, जो 99.47% है**
लघु	**:**	**3.31 लाख, जो 0.52% है**
मध्यम	**:**	**0.05 लाख, जो 0.01% से कम है**

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि एमएसएमई में सूक्ष्म और लघु इकाइयों का हिस्सा 99.99% है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि लगभग 90% सूक्ष्म इकाइयों में केवल 5 लाख रुपये तक का ही पूंजीगत निवेश (Capital Investment) है। वर्ष 2020 में भी एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया था, जिसमें निवेश को बढ़ाया गया था और टर्नओवर तत्व को भी शामिल किया गया था। इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्ष 2023–24 के लिए एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है, जो दर्शाता है कि 2015–16 के बाद एमएसएमई की संख्या से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। संभवतः, सरकार के लिए वर्ष 2020 के दौरान किए गए एमएसएमई के वर्गीकरण के संशोधन के प्रभाव का ठीक से आकलन करना संभव नहीं होगा।

संभावना है कि पहले किए गए वर्गीकरण मानदंडों में बदलाव के कारण एमएसएमई को कोई लाभ नहीं हुआ होगा। इसके अलावा, 2020 और 2021 के दौरान कोरोना महामारी ने एमएसएमई के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था और उनकी वास्तविक प्रगति का पता नहीं चल पाएगा क्योंकि इकाइयाँ अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य से काम नहीं कर रही थीं। इसलिए, एमएसएमई की विभिन्न श्रेणियों के लिए निवेश के स्तर को 2.5 गुना तक बढ़ाना और टर्नओवर के स्तर को दोगुना करना बहुत जल्दबाजी होगी। केवल उनके वर्गीकरण को संशोधित करने से कोई ठोस लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि 2020 के दौरान किए गए वर्गीकरण के पिछले संशोधन के समय निर्यात को भी कारोबार में शामिल

करने का अनुरोध किया गया था। लघु उद्योग भारती विभिन्न श्रेणियों के कारोबार की गणना करते समय निर्यात को शामिल करने के लिए फिर से दोहराना चाहेगी।

उपर्युक्त संशोधन के कारण, वर्तमान में मध्यम स्तर की इकाइयाँ अब लघु श्रेणी में आएंगी और लघु इकाइयाँ सूक्ष्म श्रेणी में आ जाएंगी, जिससे मध्यम इकाइयाँ सूक्ष्म और लघु स्तर के उद्योगों के लिए निर्धारित लाभों को साझा करेंगी। लघु उद्योग भारती को सूक्ष्म और लघु–स्तरीय इकाइयों पर उपरोक्त संवर्द्धन के प्रतिकूल प्रभाव की उम्मीद है, क्योंकि एमएसएमई का हिस्सा लगभग 99.99% हैं, जबकि मध्यम स्तर की मुट्ठी भर इकाइयाँ जो 0.01% से भी कम हैं, ऐसे लाभों को प्राप्त कर पाएँगी। इसलिए, इस स्तर पर एमएसएमई के वर्गीकरण में संशोधन से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और अनुरोध है कि फिलहाल मौजूदा मानदंडों को बहाल किया जाए।

उपरोक्त संदर्भ में वैकल्पिक रूप में हम यह भी प्रस्ताव करना चाहेंगे कि तीनों श्रेणियों अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बजट अलग–अलग आवंटित किया जाना चाहिए, जो इकाइयों की संख्या और उनके लिए आवश्यक समर्थन पर निर्भर करेगा। आवश्यक है कि सूक्ष्म और लघु इकाइयों का आवंटित बजट कम ना किया जाए।

हमारा अनुभव है कि बैंकिंग चैनल, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का हो या निजी, आम तौर पर सूक्ष्म और लघु इकाइयों को उनकी सीमित ऋण आवश्यकताओं के कारण नजरअंदाज करते हैं, जबकि बड़ी इकाइयों को ऋण और अन्य ऋण सुविधाएं आदि देना पसंद करते हैं, क्योंकि वे सीमित संख्या में ग्राहकों को वित्त सुविधाएँ देकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह तथ्य वित्त मंत्रालय के साथ–साथ आरबीआई के संज्ञान में कई बार लाया गया है, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला।

जबकि समय की मांग है कि सूक्ष्म और लघु इकाइयों को सभी प्रकार की अनुमति समयबद्ध तरीके से एक ही छत के नीचे प्रदान की जाए और उन्हें इस संबंध में एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्हें भूमि, पानी और बिजली कनेक्शन, प्रदूषण के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रेखांकित किया है कि 36% विनिर्माण और 45% निर्यात एमएसएमई द्वारा किया जाता है, जबकि 90% से अधिक सूक्ष्म इकाइयां केवल 5 लाख रुपये की पूंजी के साथ काम कर रही हैं, इसलिए, समाज के ऐसे कमजोर वर्ग को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि वे किसी भी तरह से मध्यम उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, वे ही अधिकतम रोजगार पैदा करते हैं। यह उचित होगा कि सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण इकाई के लिए विशेष रूप से एक अलग विभाग बनाया जाए, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं काफी छोटी हैं और उन्हें मध्यम स्तर के उद्यमों के साथ जोड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। इसलिए, मध्यम वर्ग और व्यापारिक संस्थानों को अलग से निपटने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मौजूदा वर्गीकरण को बहाल करके और केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक अलग विभाग बनाकर हमारे उपरोक्त निवेदनों पर अनुकूल रूप से विचार करें।

भवदीय,

घनश्याम ओझा
अ.भा. अध्यक्ष
99281 25000
president@lubindia.com

ओम प्रकाश गुप्ता
अ.भा. महामंत्री
95602 55055
gs@lubindia.com

□□□

Artificial Intelligence is Writing the Code for Humanity in this Century

New Era

Udyog Times Desk

"There is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture and so much more. We need to invest in skilling and re-skilling our people for an AI-driven future. We are developing AI applications for public good."

Narendra Modi
Prime Minister, Bharat

(Key Points of Addressing AI Action Summit Co-Chaired along with the President of France, Shri Emmanuel Macron in Paris)

PM Modi said that India is ready to share its experience and expertise to ensure that the AI future is for Good, and for All. He addressed the week-long summit, which began with the Science Days on February 6-7, followed by the Cultural Weekend on February 8-9, culminated in a High-Level Segment attended by global leaders, policymakers, and industry experts.

The High-Level Segment commenced with a dinner hosted by President Emmanuel Macron at the Élysée Palace on February 10, bringing together Heads of State and Government, leaders of international organizations, CEOs of major AI companies and other distinguished participants.

At the Plenary Session, President Macron invited Prime Minister to deliver the opening address as the co-chair of the summit. In his address, Prime Minister noted that the world was at the dawn of the AI age where this technology was fast writing the code for humanity and re-shaping our polity, economy, security and society. Emphasizing that AI was very different from other technological milestones in human history in terms of impact,

He called for collective global efforts to establish governance and standards that uphold shared values, address risks, and build trust. He further added that governance was not just about managing risks but also about promoting innovation and deploying it for the global good. In this regard, he advocated for ensuring access to AI for all, especially the Global South. He called for democratizing technology and its people-centric applications so that achieving the Sustainable Development Goals becomes a reality. Alluding to the success of India-France sustainability partnership through initiatives such as the International Solar Alliance, PM stated that it was only natural that the two

countries were joining hands to forge an innovation partnership for a smart and responsible future.

Prime Minister highlighted India's success in building a Digital Public Infrastructure for its 1.4 billion citizens based on open and accessible technology. Talking about India's AI Mission, PM noted that India, considering its diversity, was building its own Large Language Model for AI. He underlined that India was ready to share its experience to ensure that the benefits of AI reach everyone. Prime Minister announced that India will be hosting the next AI Summit. The Summit concluded with the adoption of the Leaders' Statement. The summit featured discussions on critical themes, including greater access to AI infrastructure to ensure inclusion, the responsible use of AI, AI for public interest, making AI more diverse and sustainable, and ensuring safe and trusted governance of it.

How AI is Revolutionizing India's MSME Sector- Let's dive into exactly how AI is transforming small businesses in India-and how you can start using it too.

AI is Automating Boring, Repetitive Work.

AI is Making Marketing Smarter (and More Affordable!). AI Helps Businesses Make Smarter Decisions. AI is Revolutionizing Finance & Credit Access. AI is Helping MSMEs Hire (and Retain) the Right Talent. AI is Streamlining Manufacturing & Supply Chains. AI is Strengthening Cybersecurity for MSMEs.

Artificial intelligence is changing how Silicon Valley builds startups - The old Silicon Valley model dictated that startups should raise a huge sum of money from venture capital investors and spend it hiring an army of employees to scale-up fast. Profits would come much later. Until then, head count and fund-raising were badges of honor among founders, who philosophized that bigger was better.

But Gamma is among a growing cohort of startups, most of them working on AI products, that are also using AI to maximise efficiency. They make money and are growing fast without the funding or employees they would have needed before. The biggest bragging rights for these startups are for making the most revenue with the fewest workers.

The potential for AI to let start-ups do more with less has led to wild speculation about the future. Sam Altman, the chief executive of Open AI, has predicted there could someday be a one-person company worth $1 billion...

Technology - From Space to Streets: How ISRO's Chandrayaan Tech is Transforming Daily Life The extreme conditions of space require materials that can withstand harsh environments, and ISRO's anti-corrosion coatings are now being repurposed for bridges, ships, and even cars. These specialized paints, originally designed to protect satellites and rockets, help extend the life of infrastructure and vehicles by reducing wear and tear.

ISRO's research into lightweight, high-durability materials is also benefiting the healthcare sector. Innovations in biocompatible materials could lead to improved prosthetics, medical implants, and protective gear. Additionally, space-tested water purification techniques are being adapted for household and industrial use. The software originally developed for Chandrayaan's navigation and control systems is now being adapted to enhance vehicle safety and automation.

□□□

Advantage Assam

A Successful Initiative for Investments

(The Advantage Assam 2.0 Investment & Infrastructure Summit, held in Guwahati on 25-26 February 2025, marked a significant milestone in Assam's economic growth.)

Special Report

Ashish Devda

National Joint General Secretary, LUB
ashish.deorah@yummyfoods.co.in

The summit, inaugurated by Prime Minister Shri Narendra Modi, showcased the state's robust potential as a leading investment hub in India. With proposals amounting to a record-breaking ₹4.91 lakh crore in investments and infrastructure, the event highlighted Assam's ambitious goals and strategic vision under the leadership of Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma.

The summit truly reflected CM Dr. Sarma's vision to elevate Assam as one of India's leading states. Assam's rapid development and transformation into an investment hotspot were praised by ministers, industrialists, foreign delegates, and local entrepreneurs.

PM Narendra Modi, during his address, lauded the Assam Government's efforts to bridge the state with the global economy. He remarked that it would not be long before children across India learn "A for Assam," symbolizing the state's growing significance. He retreats his commitment towards North East by saying 'Hum Aaapke sath hai' He also highlighted Assam's improving connectivity with East Asia and the emerging India-Middle East Economic Corridor. In the

8,500 Dancers performed Jhumoir Binandini to commemorate over two centuries of Assam's Tea Industry on the Grand Ceremony at Guwahati's Sarusajai Stadium.

past six years, Assam has doubled its economy from ₹2.75 lakh crore to ₹6 lakh crore. The Prime Minister also inaugurated an exhibition organized as part of the

summit, with Laghu Udyog Bharati Purvottar as the organizing partner. The exhibition featured a dedicated pavilion for Laghu Udyog Bharti with over 40 stalls.

Key Investment Announcements and MoUs

The summit attracted leading industrialists and global investors who were eager to invest in the state's future. Key announcements were made by industry giants like Shri Mukesh Ambani, Shri Gautam Adani, the Emami Group, Tata Group, and others. Investment commitments spanned across green energy, cement, tourism, healthcare, agriculture, skill development, and more.

In total, over 200 MoUs were signed across various sectors, which included prominent domestic investors such as Adani Group, Tata Power, JSW Energy, Oil India Limited (OIL), ONGC, and NRL. International partnerships were also strengthened with the Bill & Melinda Gates Foundation, Singapore's Ministry of Trade and Industry, ASEAN One Co Ltd (Japan), and Spice Lemon, further boosting Assam's global connectivity.

A key highlight was the district-level MoUs signed with an investment of ₹5,800 crore, a first-of-its-kind initiative in India. This unique model allowed small investors to sign agreements directly with district administrations, showcasing a novel approach to local-level investment and development.

The summit also saw the participation of several Union Ministers, including Shri Ashvini Vaishnav, Dr.S. Jaishankar, Shri Jyotiraditya Scindia, Shri Sarbananda Sonowal, and Shri Hardeep Singh Puri, who addressed various ministerial sessions throughout the event. The Valedictory Session was chaired by Union Minister Shri Piyush Goyal, marking the official conclusion of the two-day event.

On the occasion, the Yearly Notebook of Laghu Udyog Bharati Purvottar Prant was launched by Assam's State Industry Minister Shri Bimal Bora, highlighting the growing importance of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Assam's economy.

A New Era for Assam: "Look East, Act East, Fast East"

The summit concluded with a powerful slogan, "Look East, Act East, Fast East," symbolizing Assam's drive to become a key player in India's economic and industrial growth. Laghu Udyog Bharti praised Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma for his exemplary leadership in organizing the mega event, which successfully connected Assam to global investment and infrastructure opportunities. President Shri Ravi Sureka along with General Secretary Shri Vivek Agarwal & the entire Team of LUB Purvottar welcome the delegates in LUB pavilion and appraised the visitor delegates about the investor friendly environment in State.

□□□

राजस्थान राज्य बजट–2025
पर
औद्योगिक–नीति संबंधी विचार

शांतिलाल बालड़
प्रदेश अध्यक्ष
लघु उद्योग भारती, राजस्थान
shantilalbalar@yahoo.com

राज्य बजट–2025 में राजस्थान के औद्योगिक विकास, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार आवश्यक है। यह बजट प्रदेश के उद्योग जगत के लिए कई अवसर और चुनौतियाँ लेकर आया है।

राज्य बजट–2025 में उद्योगों के लिए प्रमुख प्रावधान:

1. लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता–

सरकार ने MSME को सशक्त बनाने के लिए नए सब्सिडी और ऋण योजनाओं की घोषणा की है, जिससे छोटे उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार में सहायता मिलेगी।

2. निवेश सीमा में वृद्धि–

MSME की परिभाषा में संशोधन करते हुएः सूक्ष्म उद्योगों के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये की गई। लघु उद्योगों के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये। मध्यम उद्योगों के लिए 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये।

3. क्रेडिट गारंटी कवर में विस्तार–

MSME को वित्तीय सहायता देने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई है, जिससे उद्यमियों को अधिक ऋण सुविधा मिलेगी।

4. औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स हब का विकास–

राज्य में 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के तहत 2 लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे, जिससे व्यापार सुगमता में

सुधार होगा।

पीएम गति शक्ति योजना को लागू किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और समन्वय बेहतर होगा।

5. विशेष औद्योगिक पार्कों की स्थापना-

कोटा में टॉय पार्क, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, और सोनीगढ़–चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक पार्क की स्थापना होगी।

उद्योगों की सुविधा के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल और प्लग एंड प्ले मॉडल लागू किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा।

6. टैक्स और रियायतें-

कुछ उद्योगों के लिए कर में राहत और GST प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं, जिससे व्यापार संचालन में सुगमता होगी।

7. हरित उद्योग और सतत विकास-

ग्रीन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन।

निजी औद्योगिक पार्कों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

MSME और उद्यमियों पर बजट के प्रभाव सरल लोन प्रक्रियाएँ लागू करने से छोटे व्यापारियों को कर्ज प्राप्त करने में आसानी होगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकारी मंजूरियों को सरल और डिजिटल किया गया है, जिससे उद्योगों की प्रशासनिक दिक्कतें कम होंगी।

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के तहत व्यापार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नीतियाँ लागू की जाएंगी।

औद्योगिक विकास को गति देने हेतु सुझाव एवं आवश्यक सुधार:

1. निवेश आकर्षित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन योजनाएँ लाई जाएं, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ राज्य में निवेश करें।

2. सरल लाइसेंसिंग प्रणाली और डिजिटल अपग्रेडेशन किया जाए, जिससे उद्योगों को कम प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़े।

3. कच्चे माल और उत्पादन लागत को कम करने के लिए विशेष नीति बनाई जाए, जिससे स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिले।

सरकार से अपेक्षाएँ एवं अनुशंसाएँ:

- MSME सेक्टर को दी जाने वाली सब्सिडी को और बढ़ाया जाए।
- औद्योगिक क्षेत्र में बिजली और लॉजिस्टिक्स को और अधिक सब्सिडी मिले।
- रोजगार सृजन के लिए विशेष औद्योगिक योजनाएँ बनाई जाएँ।

राज्य बजट 2025 में उद्योगों के विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। यदि सरकार उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप सुधार और नीतिगत समर्थन प्रदान करती है, तो राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में एक नई ऊंचाई छू सकता है।

□□□

लघु उद्योग भारती का सफल क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ में संपन्न

रिपोर्ट

उद्योग टाइम्स डेस्क

लघु उद्योग भारती का क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ में 12 जनवरी को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, दीप–प्रज्वलन के साथ किया गया

एलयूबी उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री भरत थरड ने उद्योगों की प्रमुख समस्याओं को प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान ने सभी समस्याओं पर सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में 44 लाख करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्ताव आयें हैं तथा 15 हजार करोड़ के अन्य प्रस्ताव भी निकट भविष्य में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों की समस्याओं पर सरकार संवदेनशील है और निरन्तर उद्यमी हित में कदम उठाये जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है, इस कारण बाहर के उद्यमी भी निवेश हेतु प्रोत्साहित हो रहें हैं।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में लघु उद्योग भारती, उ.प्र. के सभी संभाग अध्यक्षों ने संभागीय वृत प्रस्तुत किया। प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमन चावला व सह–कोषाध्यक्ष श्री राघव सिंह ने संगठन की वित्तीय स्थिति और नियमों के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू ने फर्रूखाबाद, कन्नौज, देवरिया, सुल्तानपुर, सीतापुर, रामपुर को पूर्ण इकाई की घोषणा करते हुए बताया कि कानपुर महिला इकाई भी गठित की जा रही है। प्रदेश कार्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था हो गयी है जिस पर प्रदेश स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की

स्थापना की जानी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा ने प्रदेश में संगठन के विस्तार की चर्चा की।

अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने कहा कि हम सभी उद्योग को परिवार समझ कर कार्य करते हैं तथा आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में भी हम सभी का सहयोग अपेक्षित है।

अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री श्री राकेश गर्ग ने भूमि व राजस्व विषयों पर उद्यमियों की समस्याओं को रखा गया।

विशिष्ट अतिथि राजस्व परिषद उ.प्र. अध्यक्ष श्री अनिल कुमार ने बताया कि भू–अभिलेख के संदर्भ में समय सीमा निर्धारित की गयी है जिसका पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उद्योग विकास बैंक सिडबी के सहायक महाप्रबंधक श्री सनोज कुमार गुंजन ने सिडबी की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लघु उद्योग भारती और सिडबी के एमओयू से प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमी लाभान्वित हो सकेंगे।

अन्तिम सत्र में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक, प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री आलोक कुमार, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष उ.प्र. लघु उद्योग निगम श्री राकेश गर्ग उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू ने प्रदेश की औद्योगिक समस्याएं जैसे नगर निगम क्षेत्रों में आवासीय के बराबर गृहकर, उद्योगों में सौर ऊर्जा संयंत्रों पर ब्याज मुक्त ऋण अथवा उपादान, निवेश मित्र पोर्टल का उच्चीकरण, प्रदूषण, फायर नियमों का सरलीकरण व औद्योगिक इकाइयों के मानचित्रों पर सभी विभागों की अनुमन्यता आदि समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित प्रदूषण विभाग की समाधान योजना, यूपीसीडा की समाधान योजना, मुरादाबाद एसईजेड की भूमि का सामान्य उद्योग में प्रयोग हेतु डीनोटिफिकेशन किया जाना आदि समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। इन समस्याओं पर प्रमुख सचिव ने उचित संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया।

उप मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया कि सभी अपेक्षित कार्य उद्यमियों के सहयोग से ही किये जायेगें। हमारे दैनिक उपयोग की सभी सामग्री छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित की जाती है और ये उद्योग ही इनकी आपूर्ति के माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती द्वारा उठाई गई सभी समस्याएं तत्काल प्रमुख सचिव स्तर से निस्तारित की जा सकेंगी।

कार्यक्रम का संचालन अ.भा. कार्यकारिणी सदस्य श्री रविंद्र सिंह और आभार लखनऊ इकाई अध्यक्ष श्री अरुण भाटिया ने ज्ञापित किया। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय तोमर, प्रदेश संयुक्त महामंत्री श्री गौरव मित्तल सहित बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित रहे।

□□□

विज्ञान भारती ने नयी पीढ़ी में किया विज्ञान का संचार

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान की समझ के विकास के लिए प्रदर्शनी भी आयोजित की

वैज्ञानिक चेतना

उद्योग टाइम्स डेस्क

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान भारती राजस्थान ने विज्ञान महोत्सव का दो दिवसीय आयोजन 27–28 फरवरी, 2025 को जयपुर में किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान के सहयोग से अपेक्स विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर श्री वी. सरवन कुमार, पद्मश्री नामित शीर्षस्थ वैज्ञानिक प्रो. आशुतोष शर्मा, कुलपति आरटीयू, कोटा प्रो. एस.के. सिंह, पूर्व कुलपति एमएलएसयू उदयपुर प्रो. जे.पी. शर्मा, पूर्व कुलपति एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर प्रो. के.के. शर्मा, निदेशक आईसीएआर बीकानेर डॉ. जगदीश राणे, जाने–माने शिक्षाविद प्रोफ़ेसर संदीप संचेती, अपेक्स यूनिवर्सिटी के चेयरमेन डॉ. रवि जूनीवाल एवं कुलपति प्रो. सोमदेव शतांशु और परिष्कार ग्रुप के निदेशक डॉ. राघव प्रकाश की गरिमामयी उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।

स्व के बोध से साकार होगा विकसित भारत का संकल्प

विज्ञान भारती के सचिव डॉ. मेघेन्द्र शर्मा ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि CSIR, CEERI, और NIA जैसे संस्थानों की सक्रिय सहभागिता से विद्यार्थियों में विज्ञान की समझ के विकास के लिए विशेष सत्रों के आयोजन के साथ विभिन्न मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि अमृत काल के इस महोत्सव में विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्व के बोध से विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। औपनिवेशिक काल में उद्योग तंत्र अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, परन्तु भारतीय वैज्ञानिक सी.वी. रमन जैसे हजारों वैज्ञानिक सेनानियों ने अपना योगदान देकर विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रतिमान स्थापित किये।

विज्ञान को सोच में लाने की जरूरत

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक नवाचारों के साथ–साथ प्रकृति के संरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने युवा शक्ति का आवाहन किया कि अन्नदाता बनें। अन्न की जरूरत सबको है किंतु अन्नदाता कोई नहीं बनना चाहता। हमारे पूर्वजों ने हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर विकास किया था। डीएसटी के सचिव वी. सरवन कुमार ने कहा कि

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह वैज्ञानिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और विज्ञान का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अपेक्स विश्वविद्यालय के कुलपति

प्रोफेसर सोमदेव शतांशु ने कहा कि विज्ञान को दैनिक जीवन में सम्मिलित कर हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

युवा प्रतिभाओं को किया सम्मानित

इस अवसर पर अनेक वैज्ञानिकों को उनके अतुलनीय योगदान और अनेक आविष्कार कर्ताओं को राजस्थान स्टेट इनोवेशन अवार्ड के अंतर्गत सम्मानित किया गया। समारोह में करीब 38 बच्चों को भी KARYA के अंतर्गत सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित क्विज, पोस्टर मेकिंग, मॉडल मेकिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।

बनाया विश्व रिकॉर्ड

कार्यक्रम में कॉइन सेल तकनीक का उपयोग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें देश भर के 50 से अधिक संस्थान और 5 स्टूडेंट्स ने एक समय में ही 18500 वोल्ट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया। कार्यक्रम का आरंभ 'रन फॉर विकसित भारत' से हुआ जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थी भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ दौड़े।

□□□

जयपुर अंचल का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित

एलयूबी जयपुर अंचल का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र पर 9 फरवरी को आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में केंद्र की बुनियादी बातें प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्र खुराना ने बताई। वर्ग प्रस्तावना प्रांत महामंत्री सुनीता शर्मा एवं अंचल कार्यों की जानकारी अध्यक्ष श्री सुधीर गर्ग ने प्रस्तुत की। अभ्यास वर्ग के महत्व पर प्रदेश महामंत्री श्री योगेंद्र शर्मा ने प्रकाश डाला। इकाइयों के वृत्त भी प्रस्तुत किये गए। द्वितीय सत्र में सोशल मीडिया की जानकारी सांगानेर महिला इकाई सचिव श्रीमती पिंकी माहेश्वरी, वेबसाइट के संचालन और सदस्यता रिकॉर्ड की प्रांत कोषाध्यक्ष श्री उदय भुवालका ने दी। एकाउंट्स के बारे में प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अरुण जाजोदिया ने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में जयपुर अंचल की 53 इकाइयों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। □□□

इंदौर सेंट्रल जेल में कैदियों को सिखाया रंग एवं गुलाल बनाना

एलयूबी मध्यप्रदेश की इंदौर महिला इकाई ने सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की जिंदगी में रंग भर दिए। इकाई अध्यक्ष श्रीमती हेमलता कुमार ने बताया कि इस अभिनव पहल से इस जेल में प्राकृतिक रंग और गुलाल बनाने का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। इस प्रशिक्षण में करीब 150 महिला एवं पुरुष कैदियों ने भाग लिया। इस दौरान चुकंदर, पालक, हल्दी, गेंदे, गुलाब एवं पलाश के फूलों से प्राकृतिक रंग और गुलाल बनाने की विधि सिखाई गई। साथ ही इन उत्पादों की पैकिंग, विपणन और बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। □□□

News Update

LUB & NSDC will set up a Skill Development Centre in Delhi NCR

Laghu Udyog Bharti, Delhi organized a meeting with

the National Skill Development Corporation (NSDC) on 18th February to discuss two key initiatives:

Conducting a Survey: The meeting aimed to plan a survey to identify the skills required by MSMEs in the Bawana Industrial area. This survey will help understand the skill gaps and needs of the industries in the region.

Setting-up a Skill Development Centre: It was also discussed for setting-up a skill development centre by NSDC in association with Laghu Udyog Bharti. This centre will provide training and facilitate skilled labour to MSMEs in the area. The goal of these initiatives is to promote skill development, enhance employability, and support the growth of MSMEs in the Bawana Industrial area.

Alwar Women Wing Joins Women Safety Campaign

LUB's Alwar Women Wing of Rajasthan State joined an initiative for women safety against cybercrimes and

atrocities. For this; an important meeting was held with Sapna Sanstha and District Police, Alwar at Moti Dungri. District Support Group gave useful suggestions for better understanding of laws for women safety.

LUB's General Secretary Smt. Alka Singh and executive members Smt. Vandana Bhatia, Smt. Ruchi Sodi and Smt. Suchi Gupta attended the meeting.

Karnataka Unit conducts Entrepreneurship Awareness Program

LUB's Karnataka State Unit and Rani Channamma University, Belagavi jointly hosted an Entrepreneurship Awareness Program for girl students at Kuvempu Hall, RCUB on 20th February. The event marked a significant milestone with the signing a MoU between Laghu Udyog Bharati & Rani Channamma University.

The MoU aims to foster entrepreneurship and self-reliance among women, students, and farmers, aligning with LUB's mission of promoting socio-economic empowerment. LUB's State Secretary Dr. Priya A. Puranik inaugurated the program. Being resource persons; Smt. Lata Hooli and Smt. Veena Jigajinni conducted insightful sessions. Vice-Chancellor Prof. C.M. Thyagaraja presided over the program.

On this occasion, Registrar Shri Santosh Kamagouda, Director IQAC Prof. J. Manjanna, Coordinator-Women Empowerment Cell Prof. Chandrika KB, and Director-Pt. Deen Dayal Upadhyaya Study Chair Prof. BS Navi were present.

The MoU is expected to pave the way for collaborative initiatives, training programs, and workshops aimed at nurturing entrepreneurial skills, creating new opportunities for students, women, and farmers across the region.

LUB & BIS Join Hands for Strengthening Industry Standards

The Bureau of Indian Standards and Laghu Udyog Bharati join hands to enhance product quality, innovation, and compliance for SMEs

in India. This important meeting was held in the presence of LUB's National General Secretary Shri Om Prakash Gupta and BIS's Scientist-E/Director Head Shri Rituraj. Both the institutions will ensure standardization, empowering industries, and unlocking global opportunities.

Cluster Initiative is taking Shape with Special Efforts of Erode Unit

An excellent cluster initiative with the support of LUB-CSIR project (8 projects) has been awarded to Erode

team members for getting into next stage of machinery installation for production. LUB's National Executive Committee Member Shri M.S. Vijayaragavan admits that a highly motivated team under the leadership of President Shri Elango and Smt. Lavanya is working and in the process of making Healthy Snacks and Drink of the FMCG market.

LUB North-East Unit Arranged an Industrial Visit for Students

Under Swavalambi Bharat Abhiyan, the Laghu Udyog Bharati North-East Unit provided an opportunity to the students and faculty members of Assam Down Town

University for visiting Megha Agro Foods in Tihu, Assam, gaining first hand insights into industry skills, market demands, and supply chain opportunities. The visit proved invaluable, bridging academia and industry while inspiring future entrepreneurs.

Goa Delegation Discussed the State of MSMEs with MD-GIDC

LUB's Delegation of Goa State paid a courtesy visit to MD-Goa Industrial Development Corporation (GIDC) IAS Shri Pravimal Abhishek and discussed the key opportunities and challenges faced by Goa MSMEs and explored possibilities for collaboration on joint

projects. The discussions focused on strengthening MSME support, enhancing infrastructure, and fostering policy initiatives to drive industrial growth in the state.

On this occasion, State President Smt. Pallavi Salgaocar, General Secretary Shri Mudit Agarwaal, Vice President Shri Jayesh Raikar, Treasurer Shri Vibhor Keny, and Joint Secretary Shri Rahul Parab were present.

SIDBI & LUB TN Signed MOU for Strengthening MSMEs

SIDBI and LUB's Tamil Nadu State Unit have signed an MoU at Chennai under the 'Program for Capacity Building' (PROMO) scheme. This partnership aimed to

strengthen the MSMEs ecosystem for LUB members by focusing on capacity building initiatives, improving MSME access to credit, and promoting overall MSME growth within the state, effectively addressing existing credit gaps in the sector. The MoU was signed by TN State Gen. Secretary Dr. Verchezhian and GM Region Head SIDBI Shri Praveenkumar. LUB's Shri Jayendran, DGM SIDBI Shri Anburaj and other officials were present.

Goa State Unit & WTC Signed a MOU for MSME Growth

LUB's Goa State Unit and World Trade Centre signed a MOU for encouraging and promoting exports amongst MSMEs and cooperation in the fields of vendor

development, investments, technology transfers, joint ventures, and collaborations. On this occasion, State President Smt. Pallavi Salgaocar, General Secretary

Shri Mudit Agarwal, Vice President Jayesh Raikar, Treasurer Vibhor Keny, Joint Secretary Shri Rahul Parob were present.

Greater Noida Unit Organised a Special Session on Tally to Empower Entrepreneurs and Accountants

LUB's Greater Noida Unit organized a seminar on "Unlocking the Full Potential of Tally" in association with Tally partners and technical teams at the DIC, Gautam Budh Nagar. The event aimed to educate entrepreneurs and accountants on the lesser-known features of Tally, enabling them to make informed

decisions and streamline their business operations.

Deputy Commissioner, DIC, Shri Anil Kumar, enlightened the audience about various beneficiary schemes initiated by the UP State Government, including subsidies on the purchase of PNG-operated or CPCB IV generators.

The seminar was coordinated by Gautam Budh Nagar Senior Vice President Shri K. P. Singh and attended by over 70 entrepreneurs and accountants, including-President Shri L. B. Singh, Vice President Shri Ashok Jain, Shri Sanjay Batra, General Secretary Shri Sachin Jain, President Noida Unit Shri Amit Goel, General Secretary Shri Anuj Jain, Shri Raj Sharma and Shri Gurdeep Singh Tuli, and many more esteemed members.

The seminar proved to be a resounding success, with participants gaining valuable insights into Tally's advanced features and their practical applications.

Derabassi Unit Conducts Blood Donation Camp

LUB's Derabassi Unit of Punjab State conducted a voluntary Blood Donation Camp and collected 82

Blood Units. In the camp, State Gen. Secretary Shri Pardeep Mongia & Secretary Shri Anil Sharma, Gen. Secretary Derabassi Shri Rahul Gupta, Secretary Shri Deepak Dhingra & Shri Sahil Garg, Shri Arvind Yuvraj, Shri Rajinder Singh, Shri Rajeev Rana, Co-Convener Women Wing Derabassi Smt. Komal Dhingra donated blood for noble cause. Certificates were also distributed to all the donors.

Punjab Delegation Discussed the Fire NOC Norms with Authority

LUB's Punjab State Delegation met ACS Local Body and Principal Secretary Department of Industries Shri Tejvir Singh IAS and discussed issues related to FIRE NOC with Compliance of Fire Safety Norms and

Delinking of Factory Licenses to FIRE NOC.

On this occasion, State President Shri Ashok Gupta, State GS Shri Pradeep Mongia, State VP Shri Ashok Sethi, Secretary Shri Mukhinder Singh, Secretary Shri Anil Sharma and Phagwara Unit Secretary Shri Arvind Bagga were present.

LUB's Jalandhar Women Wing conducted an Awareness Program

Photo 39

LUB's Jalandhar Women Wing organised an interacting session which was addressed by keynote speaker Smt. Gurmeet Kaur Assistant Director-DIC,

Jalandhar. She provided valuable information about PMEGP scheme for women entrepreneurs. She said that PMEGP aims to provide subsidised loans even to the less educated people. In urban areas; the subsidy is 25% for women entrepreneurs and in rural areas 35%. She also informed that EDP (Entrepreneurship Development Program) training can also be obtained online.

Smt. Kaur said that NSIC is going to launch a new scheme to ensure more participation of women entrepreneurs. She also informed about program related to Rural areas which provide interest free funds for self-help groups. On this occasion, State In-charge Women Work Smt. Seema Dhumal, President District Women Wing District Shri Aarti Sachdeva and other members were present.

National Org. Secretary Visits @ Pali

National Organising Secretary Shri Prakash Chandra ji observed the Labs established by Pali Unit for Sewing Machine and Computer Training. State GS Shri Yogendra Sharma & other officials were present also.

Thanks to MP MSME Minister

LUB's Ratlam Industrial Unit (MP) passed a resolution for Formal Thanks to MSME Minister, Govt. of Madhya Pradesh Shri Chaitanya Kashyap for the New Guidelines of MSME and the Action Plan for Future Agenda.

Workshop @ Guwahati

LUB's North-East Region Unit organised an important Workshop in association with National Productivity Counsil, Govt. of India on MSME Competitive (LEAN) Scheme at Guwahati on 14 February, 2025.

Union Minister Visits MSME Outreach Program @ Alwar

Punjab National Bank organized "MSME Outreach Program 2025" in Alwar where Union Minister Shri Bhupendra Yadav visited the Skill Center to be set up in Chamber Bhawan. On this occasion, LUB's Alwar Unit was invited to attend MSME-Expo on 13th February.

Budget Talk @ Siliguri

LUB's Siliguri Unit conducted a Budget Discussion in the presence Shri Sukanta Majumdar, MOS Education, Shri Raju Bista, MP Darjeeling, Shri Shankar Ghosh, MLA Siliguri, Bharat Changia, Vice President, LUB West Bengal, Shri Aditya Mitruka , GS North Bengal LUB and other entrepreneurs were present.

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते कदम

पेयजल

- ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन
- शहरी क्षेत्र में पेयजल के हेतु अमृत 2.0 योजना में 5 हजार 123 करोड़ रुपये के कार्य
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) में 5 हजार 830 करोड़ रुपये के कार्य
- 1000 ट्यूबवेल व 1500 हैंडपंप

राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP)

- 9 हजार 416 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी
- 12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएँ जारी
- 12 हजार 807 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी
- आगामी वर्ष में लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के नवीन कार्यों की शुरुआत
- Rajasthan Water Grid Corporation में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के कार्य

ऊर्जा

- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह निःशुल्क
- 6 हजार 400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
- 5 हजार 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के नए कार्यों की शुरुआत

सड़क

- 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 21 हजार किमी. नॉन-पेचेबल सड़कों में सुधार
- 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनेंगे हाईवे, बाईपास, ब्रिज एवं एलिवेटेड रोड़
- PMGSY के अंतर्गत 1600 बसावटों को जोड़ा जाएगा
- 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ
- सड़क सुरक्षा के लिए हाइवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन व 50 ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य
- 15 शहरों में रिंग-रोड के निर्माण हेतु डीपीआर बनेगी
- हाईवे पर 20 ट्रौमा सेंटर्स के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान, साथ ही 25 Advanced Life Support Ambulances भी उपलब्ध होगी

लाखों युवाओं को सौगात

- आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती
- निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार
- 500 करोड़ रुपये का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष
- 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान

ग्रामीण विकास

- मनरेगा के अन्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन
- स्वामित्व योजना में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे
- दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना में 25 हजार परिवारों को पट्टे
- पंचगौरव योजना को गति देना, 550 करोड़ रुपये का प्रावधान
- एससी/एसटी कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फण्ड की राशि बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

- 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से तथा 50 हजार को ए.सी. ट्रेन से तीर्थ यात्रा

सामाजिक सुरक्षा

- विभिन्न वर्गों के पात्र को देय पेंशन बढ़ाकर एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह
- विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना'
- बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए 35 हजार स्कूटी वितरण का लक्ष्य
- खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन Units NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ना
- 5 हजार उचित मूल्यों की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार

महिला

- 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य
- 3 लाख लखपति दीदियों को आगामी वर्ष में 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण
- मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना-आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध
- गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत

नगरीय विकास

- शहरी क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत लगभग 12 हजार 50 करोड़ रुपये के कार्य
- 500 Pink Toilets का निर्माण
- समस्त शहरों में 50 हजार स्ट्रीट लाइट्स
- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) जयपुर मेट्रो का कार्य
- शहरी क्षेत्रों में 500 नई बसें उपलब्ध
- 100 अत्याधुनिक Robotic-Three-One सीवरेज सफाई मशीनें

सुशासन

- प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केन्द्र
- Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना
- 8 नए जिलों में विभिन्न विभागीय कार्यालयों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये

हरित बजट

- राज्य का प्रथम हरित बजट (Green Budget)
- Circular Economy के व्यापक प्रसार के लिए Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025
- मिशन हरियाळो राजस्थान के अन्तर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- 250 करोड़ रुपये राशि की 'हरित अरावली विकास परियोजना'
- स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण
- एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क Induction Cook Top-Cooking System वितरण का लक्ष्य

औद्योगिक विकास

- निवेश सुविधा के लिए 'सिंगल विंडो – वन स्टॉप शॉप'
- Service Sector में निवेश हेतु Global Capability Centre (GCC) Policy
- Trading Sector के विकास एवं संवर्द्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy
- DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से लिंक कर 2 Logistics Parks

कृषि बजट

- आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण का लक्ष्य
- किसान सम्मान निधि की राशि अब 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- राजस्थान कृषि विकास योजना में 1 हजार 350 करोड़ रुपये
- गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ाकर 150 रुपये
- Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान
- आगामी वर्ष में 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान
- 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान
- आगामी वर्ष 1 लाख हैक्टेयर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव पर प्रति हैक्टेयर 2 हजार 500 का अनुदान

पशुपालन एवं डेयरी

- 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' में श्रेणीवार बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी
- एक हजार नवीन सहकारी समितियों/दुग्ध संग्रह केन्द्रों की स्थापना
- मिल्क उत्पाद, डेयरी प्लांट की प्रोसेसिंग एवं पशु आहार संयंत्रों के क्षमता वर्धन हेतु 540 करोड़ रुपये
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.50 लाख लाभार्थियों की बढ़ोतरी
- गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- समस्त जिला चिकित्सालयों में Diabetic Clinics
- गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए Day Care Centres भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ
- प्रदेश को TB मुक्त बनाना, प्रत्येक CHC पर Digital X-ray Machine, TRU-NAAT (ट्रू-नॉट) व CB-NAAT (CB-नॉट) Machine की उपलब्धता
- 'Fit Rajasthan' अभियान, 50 करोड़ रुपये के प्रावधान
- नवीन आयुष नीति, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि
- निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का 'MAA कोष' का गठन
- MAA नेत्र वाउचर योजना की शुरूआत
- 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा

कार्मिक कल्याण

- समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
- NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि
- न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
- पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

UDYOG TIMES

UDYOG TIMES OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI | 28 February - 2025 | Registration No. RAJBIL/2016/69093 Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

LUB's Haryana State Delegation met Chief Minister Shri Nayab Singh Saini for Pre-Budget Consultations. State President Shri Shubh Adesh Mittal, GS Shri (CA) Manoj Rungta & Treasurer Shri Raman Saluja were present at Chandigarh on 14 February, 2025.

MP Chief Minister Shri Mohan Yadav & MSME Minister Shri Chaitanya Kashyap released the long awaited Subsidy Amount Rs. 450 Cr. by DBT Transfer at Bhopal on 21 February, 2025.

An Exclusive Issue on Indian Dimensional Stones of Udyog Times was released by MoS Industry Rajasthan Shri K.K. Vishnoi, LUB's National President Shri Ghanshyam Ojha & National Secretary Shri Naresh Pareek at STONA Exhibition, Bangalore on 12 January, 2025.

A MOU was signed by Laghu Udyog Bharati and Atal Innovation Centre of Guru Gobind Singh Indraprastha University in the presence of National GS Shri O.P. Gupta and National Secretary Smt. Anju Bajaj at New Delhi on 17 February, 2025.

LUB's National Core Group Meeting was conducted at Delhi Head Quarter in the presence of Organising Secretary Shri Prakash Chandra ji, President Shri Ghanshyam Ojha and GS Shri O.P Gupta at New Delhi on 24 February, 2025.

Follow us

lubindia | lubindia
@lubBharat | lub.india
laghu-udyog-bharati

LUB's Monthly Magazine Published by OP Mittal Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019